

गन्ना किसानों को राहत देने में सरकार अब तक नाकाम

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।

310-315

गन्ना किसानों को राहत मुहैया कराने में केंद्र सरकार की कवायद अब नाकाम साबित होती दिख रही है। इसकी वजह प्रति टन 55 रुपये की आर्थिक सहायता पहुंचाने में चीनी मिलों पर रखी गई निर्यात की शर्त है। मिलें 20 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए आगे नहीं आई हैं और इसकी उम्मीद भी नहीं है।

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक, चीनी मिलें उत्पादन लिंक आर्थिक सहायता की घोषणा के बावजूद निर्यात नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए मिलों को 20 लाख टन चीनी का निर्यात करना अनिवार्य है। अभी तक कोई भी चीनी मिल निर्यात करने के लिए सामने नहीं आई है। लिहाजा, सरकार बफर स्टॉक बनाने की

**लाख टन रिकॉर्ड चीनी
उत्पादन का अनुमान चालू
पेराई सीजन में**

योजना पर काम कर रही है।

**30 लाख टन का बफर स्टॉक
बनेगा :** मंत्री ने बताया कि 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाया जाएगा। इसके अलावा, सरकार गन्ना किसानों को राहत मुहैया कराने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। इनमें एथेनॉल पर जीएसटी कम करने और चीनी पर शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव जीएसटी परिषद को भेजा गया है। हालांकि, पिछली बैठक में दोनों ही मुद्दों पर परिषद ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और मामला टल गया।

Amar Ujala

01-06-16

